ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-10* November- 2017
Innovation The Research Concept

राजस्थान में उच्च शिक्षा बदलाव हेतु कुछ सुझाव

सारांश

राजस्थान में उच्च शिक्षा की विकास यात्रा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से प्रारम्भ होती है, जबकि मात्र 07 महाविद्यालय उच्च शिक्षा देने का कार्य करते थे।[1] तब से अब तक राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। वर्तमान में इस प्रगति के आकलन का देश में सर्वश्रेष्ठ मापदण्ड 'ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (Aishe Survey) है। इस कारण प्रस्तुत आलेख में अनेक जगह 'आइशी सर्वे' (ऑल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के वर्ष 2015–16 के परिणामों से उदाहरण लिए गए हैं।

मुख्य शब्द : उच्च शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीन शिक्षण विधियां।

अखय राज मीणा
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
झालावाड़

सुनिल मीणा
व्याख्याता,
भौतिक शास्त्र विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
झालावाड़

प्रस्तावना

राजस्थान में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति

राजस्थान में उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राज्य मानव संसाधन व आधारभूत ढाँचे की उपलब्धता, शिक्षा ऋण, पीपल–टीचर अनुपात तथा जेण्डर पैरिटी इण्डेक्स जैसे अनेक मानको में पिछड़ा हुआ है। वर्ष 2015–16 के आइशी सर्वे में देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रान्त राजस्थान कॉलेजों की संख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर रहा है। इसके 3705 संस्थानों ने इस सर्वे में भाग लिया है। इस दृष्टि से प्रथम तीन स्थानों पर क्रमशः उत्तर प्रदेश (7495), महाराष्ट्र (7115) व कर्नाटक (5284) हैं।[2] बेंगलूरू जिला कॉलेजों की संख्या की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है, जहाँ 790 कॉलेज हैं। हमारा जयपुर जिला 616 कॉलेजों के साथ दूसरे स्थान पर है।[3] जनसंख्या के अनुपात में कॉलेजों की संख्या देखें तो राजस्थान में प्रत्येक लाख की आबादी पर 35 कॉलेज हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 28/– प्रति लाख है। इस मामले में राजस्थान हरियाण के साथ सातवें स्थान पर है।[4] राजस्थान मे 18–23 वर्ष आयु वर्ग में वर्ष 2015–16 में उच्च शिक्षा में 88 लाख बच्चे नामांकित हुए, जिनमें 65.07 प्रतिशत स्नातक में, 29.1 प्रतिशत स्नातकोत्तर में तथा मात्र 0.4 प्रतिशत डॉक्टरेट में नामांकित हुए।[5] भारत में सकल नामांक दर 24.5 प्रतिशत है, जबकि राजस्थान में इससे बहुत कम 20.2 प्रतिशत। महिला नामांकन दर देश में 23.5 प्रतिशत है, जबकि राजस्थान में मात्र 18.5 प्रतिशत। राजस्थान में अजा व अजजा की नामांकन दर क्रमशः 15.2 व 15.2 प्रतिशत है।[6] भारत में जेण्डर पैंरिटी इंडेक्स 0.92 है, जबकि राजस्थान में इससे कम 0.85 है। पीपुल टीचर रेषों (PTR) राजस्थान में 24 है जो राष्ट्रीय औसत (20) से अधिक है, परन्तु इस मामले में प्रथम स्थान रखने वाले उत्तर प्रदेश (34) से हम 10 अंक पीछे हैं।[7] हमारे यहा वर्ष 2015–16 में कुल 856 विदेशी विद्यार्थी उच्च शिक्षा में नामांकित थे, किन्तु इनमें से पी.एच.डी. कोर्स में मात्र 05 विद्यार्थी नामांकित थे।[8]

इस प्रकार राजस्थान में उच्च शिक्षा में कुछ खामियाँ हैं, तो कुछ खूबियाँ। अब पहले हम खामियों की चर्चा करेंगे, फिर खूबियों (नवाचारों) की।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत आलेख में 'राजस्थान में उच्च शिक्षा : बदलाव हेतु कुछ सुझाव' शीर्षक के अन्तर्गत तीन भागों में अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं।

1. भाग – 1. में राजस्थान में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर विचार प्रकट किए गए हैं।
2. भाग – 2. में राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को इंगित किया गया है।
3. भाग – 3. में जो सबसे महत्वपूर्ण है, राजस्थान में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

राजस्थान में उच्च शिक्षा की खामियाँ

देश में उच्च शिक्षा में कई खामियाँ हैं, जो राजस्थान में भी परिलक्षित होती है। लेखक द्वय ने इन खामियों को इंगित किया है। इनमें से कुछ खामियाँ निम्नवत् हैं :–

राजस्थान में शिक्षा का कम बजट

देश में उच्च शिक्षा पर खर्च बहुत कम है। यह जीडीपी का महज 0.6 प्रतिशत हैं, जबकि फिनलैण्ड और स्वीडन में यह क्रमशः 1.6 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत है।[9] 8 मार्च, 2017 को राजे सरकार ने सूबे का 67 वाँ बजट (वर्ष 2017–18) पेष किया, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए 1399 करोड़ रुपए का प्रावधान है।[10] द वैल्यू ऑफ एजुकेशन :– एचएसबीसी ने 02 जुलाई, 2017 को स्कूल/कॉलेज की शिक्षा पर खर्च पर एक सर्वे रिपोर्ट जारी की। सर्वे में कुल 15 देश शामिल हैं। सर्वे के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई पर खर्च के मामले में भारत 13 वें स्थान पर है। यानी सिर्फ फ्रांस और मिस्त्र दो देशों से ही हम आगे हैं। सर्वे के मुताबिक भारत में अभिभावक सालाना रु. 12 लाख से ज्यादा अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। सर्वे में हांगकांग प्रथम स्थान पर (रु 85.90 लाख) है। सर्वे में फ्रांस अन्तिम स्थान पर है।[11]

नैक एक्रिडिएषन

राजस्थान की 70 कॉलेजों में नैक एक्रिडिऐषन किया गया है। इनमें केवल 07 कॉलेजों को 'A' ग्रेड प्राप्त हुआ है।[12] हमने गर्वनमेंट पीजी कॉलेज,झालावाड़ में नैक एक्रिडिएषन के लिए शैक्षिक और अशैक्षिक स्टॉफ की सक्रियता देखी है। संरचनात्मक ढाँचे व स्टाफ की कमी की वजह से माननीया मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के क्षेत्र का और उस जिले का यह सबसे बड़ा कॉलेज 'A' ग्रेड से वंचित रह गया और इसे 'B' ग्रेड पर संतोष करना पड़ा। यही हाल राजस्थान के अधिकांष कॉलेजों का है।

नेषनल हायर एजुकेशन रैंकिंग फ्रेमवर्क –2017 (एनआईआरएफ)–2017)

वर्ष 2017 के नेषनल हायर एजुकेशन रैंकिंग फ्रेमवर्क(एनआईआरएफ) में देश की टॉप –100 यूनिवर्सिटीज में राजस्थान की मात्र 4 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। ये हैं :–

1. बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी एण्ड साइंस (बिट्स पिलानी,) 13 वीं रैंक),
2. वनस्थली विद्यापीठ(निवाई, टोंक, 53 वीं रैंक)
3. राजस्थान युनिवर्सिटी ऑफ वेटरीनरी एण्ड एनिमल साइंस(रुवास – 68 वीं रैंक)
4. राजस्थान यूनिवर्सिटी (जयपुर –79वीं रैंक)।[13]

रोजगार का अभाव

हर वर्ष लाखों की संख्या में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारक निकलते हैं, लेकिन रोजगारपरकता मात्र 10 प्रतिशत है। लगभग 90 प्रतिशत के पास कोई उपयुक्त रोजगार नहीं है।[14] ऐसा डिग्रीधारक समाज, परिवार व सरकार के लिए भार है जो कि आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है।[15] प्रो0 गोवर्धन मेहता के अनुसार, ''प्रतिवर्ष 50 से 60 लाख विद्यार्थी डिग्री के लिए प्रवेश लेते हैं, लेकिन उनको रोजगार मिलना बड़ी चुनौती है। हम 'वर्थलेस ग्रेजुएट' (अनुपयोगी स्नातक) तैयार कर रहे हैं।''[16]

पाठ्यक्रम में खामी

हमारे नीतिकारों द्वारा आजादी के बाद मैकाले के मैट्रिक सिस्टम से आगे उच्च शिक्षा का ढ़ांचा ठीक से खड़ा नहीं किया गया। इस कारण उच्च शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार मात्र हो गई है। दूसरे शब्दों में, 6 वीं कक्षा में विद्यार्थी जिस रूप में अकबर, षाहजहाँ पढ़ते हैं, उसी रुप में कक्षा 12 से 14 तक पढ़ते है।[17]

राजस्थान में उच्च शिक्षा में अनिवार्य विषयों की भरमार है, जिनमें अनिवार्य हिन्दी, अनिवार्य अंग्रेजी, नैतिक शिक्षा, कम्प्यूटर एप्लीकेषन, पर्यावरण शिक्षा मुख्य है। ये सभी विषय अधिकतर स्नातक पाठ्यक्रमों में पार्ट – I के साथ शामिल किए गए हैं। यदि इन अनिवार्य विषयों को ईमानदारी से पढ़ें–पढ़ाएँ, तो अकेले इनको पढ़ाने के लिए ही एक साल के समय की आवश्यकता होगी। ऊपर से ऐच्छिक विषय भी विद्यार्थी को पढ़ने हैं। एक गलती यह भी है कि अनिवार्य विषयों में विद्यार्थी को केवल पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, जो वह जैसे तैसे ले आता है। उसे इन विषयों को ध्यान से पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। फलतः हमारा अनिवार्य विषयों का कोन्सेप्ट अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है।

मूल्यांकन प्रक्रिया में खामी

शिक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कारक होती है जो हमारी प्रतिभा प्रोत्साहन और गुणावलोकन में मदद करती है। किन्तु हमारे यहाँ मूल्यांकन प्रक्रिया की वैज्ञानिकता संदेह के घेरे में है। इस यांत्रिक प्रक्रिया में तोता–रटंत सोच को बढ़ावा दिया गया है जिससे न तो विद्यार्थी के वैषिष्ट्य का पता चल पाता है और न ही उसमें विषलेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास हो पाता है। ऊपर से हमारी जुगाड़ टैक्नोलॉजी अपनी करामात दिखा देती है जैसा की पिछले दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय में नजर आया।

आधारभूत ढाँचे की कमी

राजस्थान में राजनीतिक दबाव के चलते अनेक नये महाविद्यालय दूरस्थ क्षेत्रों खोले गये हैं। इन नये महाविद्यालयों में आधारभूत सरंचना बहुत ही खराब है। विद्यार्थी तो दूर कई महाविद्यालय मे तो शिक्षकों के बैठने तक के लिए उचित फर्नीचर नही हैं। इसके अलावा कम्प्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन जैसी कई मूलभूत सुविधाओं की कमी आम बात है।

फैकल्टी का अभाव

राजस्थान में शिक्षकों के स्वीकृत पदों और भरे हुए पदों में बहुत बडा अन्तर हैं । इस कारण अनेक विषय वर्षभर कक्षाओं के लिए तरसते रहते हैं। फिर हमारी तदर्थ व्यवस्था से उत्पन परायेपन की भावना शिक्षक को कालांषो में अनमने भाव से धकेलती है। सहायक स्टाफ पर्याप्त न होने के कारण उनके कार्य भी शिक्षकों को करने पड़ते हैं। इस वजह से भी पढ़ाई प्रभावित होती है।

निजीकरण

राजस्थान में वर्ष 2015–16 के आइशी सर्वे में 2392 कॉलेज शामिल हुए, जिनमें से 1904 प्राइवेट तथा 484 सरकारी हैं।[18] इस प्रकार निजीकरण की तरफ शिक्षा अत्यधिक तेजी से फैली है। फलतः उच्च शिक्षा में माफिया पैदा हो गए हैं।[19] उच्च शिक्षा मे निजीकरण से लाभ का तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है तथा शोध व गुणवत्ता का तत्व पीछे छूट गया है। पीपीपी की सकल्पना के आने से यह खामी बढ़ेगी ही।

राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार

भारत और विशेषतः राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नित नये प्रयोग और सुधार किए जा रहे हैं, ताकि यह मरु प्रदेश बौद्धिकता के क्षेत्र में प्रगति के नये आयाम स्थापित कर सके। नित–नवाचारों द्वारा प्रदेश के विकास पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से संभागीय आधार पर विश्वविद्यालयों का गठन किया जा रहा है। सातों संभागों में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।[20] बजट भाषण वित्त वर्ष 2016–17 में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने घोषणा की है कि 'स्टेट हायर एजुकेशन प्लान' (SHEP) तैयार कर 8 वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चरणबद्ध रूप विकास किया जाएगा। योजना के तहत् आगामी वर्ष में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 173 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया।[21]

केन्दीय बजट 2016–17 में भी उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेन्सी (हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेन्सी = हेफा) के गठन की घोषणा की गई। बजट में रु 1000 करोड़ की आरंभिक पूँजी वर्ष 2016–17 में इस एजेन्सी की स्थापना हेतु रखी गई। इसकी निधियों का इस्तेमाल सरकार देश की षीर्षक शैक्षणिक संस्थाओं में आधारभूत ढाँचे के सुधार के लिए करेगी।

रूसा(राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान)

यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जो वर्ष 2013 में प्रारम्भ की गई। इस योजना का उद्देष्य राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थाओं को रणनीतिक कोष उपलब्ध करवाना है।[22] रुसा का फंडिंग पैटर्न इस प्रकार है :–

क्र.सं.	राज्य – श्रेणी	फण्डिंग पैटर्न (केन्द्र : राज्य)
1.	सामान्य श्रेणी राज्य	60 % 40 प्रतिशत
2.	विशेष श्रेणी राज्य	90 % 10 प्रतिशत
3.	केन्द्र शासित प्रदेश	100 % 00 प्रतिशत

राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा परिषद रूसा के लिए नोडल एजेन्सी है।[23]

दसारी योजना

रूसा के अन्तर्गत संचालित दसारी योजना एक अच्छी पहल है। इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणित, रीजनिंग तथा सामान्य अध्ययन की कोचिंग सुविधा स्व वित्त पोषण के आधार पर प्रदान की जाती है।

ई–कोर्सेज

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से उच्च शिक्षा में ई–कोर्सेज उपलब्ध करवा रही है। जैसे – स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से विभिन्न कम्प्यूटर कोर्सेज(लिबरे ऑफिस के सम्बन्धित ; हेलो इंग्लिश एप 'अपर' (UPER) ; मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्नातकोत्तर कक्षाओं के 57 विषयों के ई–कोर्स यूजीसी के पोर्टल, इंफिलिबनेट और ई–पाठषाला पर उपलब्ध कराए हैं। विद्यार्थी, शिक्षक और संस्थाएँ इनका अध्ययन–अध्यापन कर सकेंगे।[24] केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार मोबाइल एप 'स्वयं' (SWAYAM) पर 250 उपयोगी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

रेग्यूलेशन – 2017

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी एक समिति की अनुशंसा पर साहित्य की चोरी रोकने के लिए 'रेग्यूलेशन – 2017' तैयार किया है। इसमें प्रावधान है कि साहित्य, रिसर्च की चोरी पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। प्रावधान[25] :–

क्र.सं.	साहित्यिक चोरी (कंटेट की चोरी) का %	सजा का प्रावधान
1.	10 % तक	कोई सजा नहीं ।
2.	40 % तक	छात्र को कोई अंक नहीं मिलेगा।
3.	60 % तक	छात्र का रजिस्ट्रेषन रुकेगा।
4.	60 % से अधिक	लिखित सामग्री हटेगी। साथ ही तीन साल तक सामग्री के प्रकाशन पर रोक रहेगी।

इस रेग्यूलेशन पर 30 सितम्बर, 2017 तक रिसर्च स्कालर्स, शिक्षक, विशेषज्ञ अपनी–2 राय भेज सकते थे।[26]

शिक्षण संस्थानों की स्वच्छता रैंकिंग

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पहली बार देश के 174 शिक्षण संस्थानों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की है। देशभर के 4500 शिक्षण संस्थानों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। हरियाणा के सोनीपत की ओ.पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी इस सूची में पहले स्थान पर है।[27] राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि इस सर्वे में जयपुर का मणिपाल विश्वविद्यालय देशभर में दूसरे स्थान पर रहा है। इस विश्वविद्यालय में पानी से लेकर कचरा और कागज सब कुछ रिसाईकिल होता है। यहां कचरे से बायोगैस बनाई जाती है।[28] इस संस्थान में दिन में तीन–चार बार सफाई होती है और इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। हर महत्वपूर्ण स्थान पर कचरा पात्र रखा हुआ है। सब्जियों के लिए किचन–गार्डन है। साथ ही 850 किलोवॉट बिजली पैदा करने वाले सोलर पैनल लगे हैं। कैंपस में वाहनों का प्रवेश बन्द है। यहां प्रवेश लेने वाला तथा कैंपस छोड़कर जाने वाला छात्र एक पौधा लगाता है। [29] मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर षहर से करीब 32 किलोमीटर दूर जयपुर–किशनगढ़ हाइवे पर दहमी कला गाँव में बना है। करीब 154 एकड़ में फैले इस कैंपस की डिजाइनिंग मषहूर वास्तुविद हफीज कॉन्ट्रेक्टर ने की थी।[30]

उच्च शिक्षण संस्थाओं में विदेशी फैकल्टी को मंजूरी

केन्द्रीय मावन संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में बिना किसी रोक–टोक के विदेशी प्राध्यापकों की मदद लेने की अनुमति प्रदान की है। मंत्रालय ने अगले शैक्षणिक सत्र में करीब 800 विदेशी प्राध्यापकों को भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने का लक्ष्य तय किया है।[31] यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार

भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान विदेशी प्राध्यापकों को अंषकालिक और पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन यह संख्या 20 फीसद से ज्यादा नहीं होगी। मौजूदा व्यवस्था के तहत् किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान को विदेशी प्राध्यपकों को बुलाने के लिए यूजीसी और मंत्रालय स्तर पर अनुमति लेनी होती है जिसमें संस्थानों का काफी समय खराब होता है। साथ ही उन्हें लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।[32] मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विदेशी प्राध्यापकों के लिए मांग देने हेतु 'ज्ञान' (ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क) नामक पोर्टल शुरू किया है।[33] इससे पहले केन्द्र सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी पाठयक्रम संचालित करने की अनुमति दी थी, जिसके तहत वे बिना यूजीसी की मंजूरी के विश्वविद्यालयों में नए पाठयक्रम, कार्यक्रम और अलग से फैकल्टी शुरु कर सकते हैं। इसके तहत इन्हें सिर्फ डिग्री पाठयक्रमों के लिए यूजीसी से अनुमति लेनी होती है।[34] विदेशी प्राध्यापकों के आने से भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में बड़े स्तर पर सुधार होगा। साथ ही भारतीय विश्वविद्यालयों को लेकर विदेशों में भी रुझान बढ़ेगा।

राजस्थान में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव

उच्च शिक्षा में पोर्ट सिस्टम लागू करना चाहिए

हमारी शिक्षा व्यवस्था में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। इस कारण जिधर भी रोजगार दिखाई देता है, हमारा विद्यार्थी उधर ही दौड़ पड़ता है। यही कारण है कि स्नातक कला के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में से मात्र 50–60 प्रतिशत ही स्नातक पूर्ण कर पाते हैं। उदाहरण के लिए सत्र 2017–18 में राजकीय महाविद्यालय, मनोहरथाना में बी.ए. पार्ट – प्रथम में प्रवेश लेने वाले 192 विद्यार्थियों में से 30 सितम्बर 2017 तक ही 11 विद्यार्थी टी.सी. ले चुके। गत वर्ष प्रवेश लेने वाले 200 में से मात्र 117 विद्यार्थी इस वर्ष बी.ए.पार्ट द्वितीय में हैं। वहीं, सत्र 2015–16 में बी.ए.पार्ट प्रथम में प्रवेश लेने वाले 200 विद्यार्थियों में से इस वर्ष मात्र 97 बी.पार्ट. तृतीय में हैं। कोर्स छोड़ने वाले अधिकांष बीएसटीसी या अन्य कोर्सों में प्रवेश लेने चले गये। यह प्रक्रिया मानव संसाधन तथा आर्थिक संसाधनों की बर्बादी है। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिविलिटी लानी होगी। मेरा सुझाव है कि हमें अमेरिकी सिस्टम की तरह विद्यार्थी को इंस्टीट्यूट बदलने तथा समयान्तराल लेने की छूट देनी चाहिए। एक सेमेस्टर या एक वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त विद्यार्थी को गेप लेने या इंस्टीट्यूट बदलने की छूट दी जाए। इस प्रक्रिया को पोर्ट सिस्टम द्वारा आसान बनाया जा सकता है। हम विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के समय एक बायोमैट्रिक कार्ड देंगे, जो आधार से लिंक होगा तथा उसमें विद्यार्थी का पूरा शैक्षणिक विवरण होगा। यदि विद्यार्थी अगले सेमेस्टर में किसी दूसरे संस्थान में प्रवेश लेना चाहे, तो उसे प्रवेश देना चाहिए, बषर्ते वह विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ आवष्यक न्यूनतम प्राप्तांक रखता हो। इससे विद्यार्थी का समय व श्रम बच सकेगा। साथ ही देश के किमती संसाधन बचेंगे।

उच्च शिक्षा में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाए

ग्रेडिंग सिस्टम से अंको की प्रतिस्पर्धा कुछ कम होगी तथा एक–दो अंको के अन्तर से नर्वस होने वाला विद्यार्थी अनावश्यक तनाव से बच सकेगा।

उच्च शिक्षा में सेमेस्टर प्रणली लागू हो

आज हमारी उच्च शिक्षा वन–वीक सीरीज और पास बुक्स के जाल में फंस गई है। इस कारण विद्यार्थी या तो कालांषों में नहीं आता है और आता है तो क्लास में अनुषासित नहीं रहता है। ऐसे में सेमेस्टर सिस्टम कारगर हो सकता है। थोड़े –2 समयान्तरण पर परीक्षाएं होने से विद्यार्थी शिक्षक के संपर्क में रहने और पढ़ने को बाध्य होगा।

उच्च शिक्षा में बहुस्तरीय मूल्यांकन व्यवस्था को अपनाया जाए

उच्च शिक्षा में वार्षिक परीक्षा प्रणाली की बजाय बहुस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू की जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय की तर्ज पर आन्तरिक मूल्यांकन को अपनाया जा सकता है। साथ ही नकल की प्रवृति रोकने के लिए सावधिक परीक्षाओं में बाहरी पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं। ओरल टेस्ट भी मूल्यांकन का भाग बने।

उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बीच कम्युनिटी कॉलेज प्रणाली अपनायी जाए

हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषयों की भरमार हैं और ये ऐसे विषय हैं जिनका राष्ट्र की आवश्यकताओं की दृष्टि से ज्यादा महत्व है, किन्तु वर्तमान व्यवस्था में इन विषयों में मात्र उत्तीर्णांक लाना जरुरी है और यदि विद्यार्थी यह भी नहीं ला पाए, तो आगामी कक्षाओं के साथ इन्हें उत्तीर्ण कर सकता है। यह व्यवस्था गलत है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी अनिवार्य विषयों को गंभीरता से नहीं लेता है। फलतः इन विषयों को पाठ्यक्रम में रखने का उद्देष्य होता है? उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः मेरा सुझाव है कि राजकीय महत्व के विषयों की पहचान की जाए, जो मेरी दृष्टि में निम्न हो सकते हैं :–(i) अंग्रेजी : व्यावहारिक ज्ञान, (ii) हिन्दी : व्यावहारिक ज्ञान, (iii)नैतिक शिक्षा, (iv) पर्यावरणीय शिक्षा, (v) कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान, (vi) दैनिक विज्ञान, (vii) दैनिक गणित, (viii)सांस्कृतिक इतिहास, (ix) भारतीय संविधान, (x) राजस्थान के सन्दर्भ में राजस्थान अध्ययन, (xi) परिवहन जागरुकता, (xi) सेक्स एजुकेशन(अष्लीलता रहित ज्ञान), आदि। यह सूची और पाठ्य सामग्री इतनी बड़ी है कि इसके अध्ययन के लिए कम से कम एक वर्ष की समायावधि की आवश्यकता होगी। अतः मेरा सुझाव है कि कक्षा 12 के बाद प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इन विषयों का शिक्षण आवष्यक हो। इस हेतु एक वर्षीय पाठ्यक्रम जिसमे दो सेमेस्टर हो, के रूप में इन विषयों को पढ़ाया जाए। इस हेतु कम्युनिटी कॉलेज खोले जाएं, जिनमें ये विषय पढ़ाये जाएं।

कम्यूनिटी कॉलेज का एक वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को ही स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश मिले तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में केवल ऐच्छिक विषय पढ़ाये जाएं। स्नातक में प्रवेश के

लिए कक्षा 12 तथा कम्यूनिटी कॉलेज कोर्स के अंकों को 70:30 के रूप में आधार बनाया जाए।

उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ना

शिक्षण संस्थाओं को उद्योगों से अटैच किया जाए। औद्योगिक संगठन शिक्षण संस्थानों की आर्थिक जरुरतें परी करें तथा शिक्षण संस्थाएं उद्योगों को मानव संसाधन के रूप में मदद दें। इस हेतु दो घंटे का कालांष उद्योग में शारीरिक या मानसिक श्रम का हो सकता है। ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिनमें कक्षा 10 के बाद प्रवेश लिया जाता हो, उनमें अनिवार्य विषयों की पढ़ाई व्यावसायिक पाठ्यक्रय पूर्ण करने के बाद करवायी जाए। इससे देश की अनेक सामाजिक–आर्थिक समस्याएं हल होंगी।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा में कुछ कमियां हैं तो कुछ नवाचार भी हो रहे हैं। हमें नवाचारों को प्रोत्साहित करना है तथा खामियों को दूर करना है। हम आशान्वित हैं कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए हमारे द्वारा दिये गये सुझाव कारगार सिद्ध होंगे। साथ ही शिक्षा में क्रांति ला रहा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण रुझान है – सूचना प्रौद्योगिकी, विशेषतः इंटरनेट। खान अकादमी जैसे मंच भविष्य की लहर हैं।[35] क्लाउड आधारित नवीन शिक्षण विधियां शिक्षा–क्रांति के नये हथियार हैं, जैसे– वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल लर्निंग इत्यादि। अतः हमें शीघ्राती–षीघ्र इन्हें अपना लेना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *डॉ0 सुभाष गंगवाल, ओपिनियन – राजस्थान में उच्च शिक्षा की दशा, दैनिक नवज्योति, 29 अप्रेल, 2017, वेबसाइट– दैनिक नवज्योति डॉट नेट।*
2. *आइशी सर्वे रिपोर्ट – 2015–16*
3. *आइशी सर्वे रिपोर्ट – 2015–16*
4. *आइशी सर्वे रिपोर्ट – 2015–16*
5. *आइशी सर्वे रिपोर्ट – 2015–16*
6. *आइशी सर्वे रिपोर्ट – 2015–16*
7. *आइशी सर्वे रिपोर्ट – 2015–16*
8. *आइशी सर्वे रिपोर्ट – 2015–16*
9. *प्रो.(डॉ0) राम लखन मीणा, देश में उच्च शिक्षा में राजस्थान की स्थिति और भी बदतर है, जनवरी, 2016,एचटीटीपीः//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट रिसर्चगेट डॉट नेट।*
10. *राजस्थान बजट : शिक्षा के लिए खुला राजे सरकार का पिटारा, स्वास्थ्य सेवाओं का भी रखा ख्याल, दैनिक जागरण, वेबसाइट–एम डॉट जागरण डॉट कॉम, 08 मार्च, 2017*
11. *दैनिक भास्कर , कोटा, 03.07.2017*
12. *कवर स्टोरी : राजस्थान हायर एजुकेशन एम्ब्रेसिंग चेंज फॉर न्यू एरा ऑफ अपॉर्चूनिटी, वेबसाइट– डिजिटललर्निंग डॉट इलेट्सऑनलाइन, पब्लिष्ड– अगस्त 10, 2017*
13. *कवर स्टोरी : राजस्थान हायर एजुकेशन एम्ब्रेसिंग चेंज फॉर न्यू एरा ऑफ अपॉर्चूनिटी, वेबसाइट– डिजिटललर्निंग डॉट इलेट्सऑनलाइन, पब्लिष्ड– अगस्त 10, 2017*
14. *डॉ0 सुभाष गंगवाल, ओपिनियन – राजस्थान में उच्च शिक्षा की दशा, वही।*
15. *डॉ0 सुभाष गंगवाल, ओपिनियन – राजस्थान में उच्च शिक्षा की दशा, वही।*
16. *उच्च शिक्षा में राजस्थान की प्रगति – राजीव स्वरूप, अजमेरनामा डॉट कॉम, 20 सितम्बर, 2017*
17. *स्पेशल स्टोरी – अभिवन शिक्षा : उच्च शिक्षा हमारे महाविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय, वेबसाइट – डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट राजस्थान शिक्षा डॉट कॉम, जुलाई 12, 2016*
18. *आइशी सर्वे रिपोर्ट – 2015–16*
19. *डॉ0 सुभाष गंगवाल, ओपिनियन – राजस्थान में उच्च शिक्षा की दशा, वही।*
20. *डॉ0 सुभाष गंगवाल, ओपिनियन – राजस्थान में उच्च शिक्षा की दशा, वही।*
21. *नकुल देवर्षि, राजस्थान बजट : 2016–17 : शिक्षा – उच्च शिक्षा में ये हुई 24 बड़ी घोषणाएं, राजस्थान पत्रिका, 8 मार्च, 2016, एम डॉट पत्रिका डॉट कॉम।*
22. *कवर स्टोरी : राजस्थान हायर एजुकेशन एम्ब्रेसिंग चेंज फॉर न्यू एरा ऑफ अपॉर्चूनिटी, वही।*
23. *कवर स्टोरी : राजस्थान हायर एजुकेशन एम्ब्रेसिंग चेंज फॉर न्यू एरा ऑफ अपॉर्चूनिटी, वही।*
24. *दैनिक भास्कर , 23 मार्च, 2017*
25. *राजस्थान पत्रिका, कोटा, 21 सितम्बर, 2017*
26. *राजस्थान पत्रिका, कोटा, 21 सितम्बर, 2017*
27. *राजस्थान पत्रिका, कोटा, 15 सितम्बर, 2017*
28. *दैनिक जागरण (ई–पेपर), 23 सितम्बर, 2017*
29. *दैनिक जागरण (ई–पेपर), 23 सितम्बर, 2017*
30. *दैनिक जागरण (ई–पेपर), 23 सितम्बर, 2017*
31. *दैनिक जागरण (ई–पेपर), 04 नवम्बर, 2017*
32. *दैनिक जागरण (ई–पेपर), 04 नवम्बर, 2017*
33. *दैनिक जागरण (ई–पेपर), 04 नवम्बर, 2017*
34. *दैनिक जागरण (ई–पेपर), 04 नवम्बर, 2017*
35. *राजीव मल्होत्रा, अमेरिकी उच्च शिक्षा क्षेत्र में संकटः भारत के लिए अवसर व खतरे, अप्रेल 19, 2017, वेबसाइट – डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जागृतभारत डॉट कॉम।*